

प्रश्नक,

राधा रतूडी,

मुख्य सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

आई0सी0डी0एस0,

उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग,

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रीयित योजनाओं की वित्तीय

स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1833/विबिध बजट-4330/2017-18 दिनांक 21.09.2017 के

संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आई0सी0डी0एस0 उल्लेखित एवं

राज्य हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न केन्द्रीयित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश एवं

राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान संख्या-15 के अन्तर्गत

ईन-राशि ₹ 1964024 हजार (एक अरब छियानबे करोड़ बालीस लाख चौबीस हजार मात्र) अनुदान

संख्या-30 में इन-राशि ₹ 193395 हजार (उन्नीस करोड़ तैलीस लाख पियानबे हजार मात्र) एवं

अनुदान संख्या-31 में इन-राशि ₹ 30327 हजार (कू तीन करोड़ तीन लाख सत्ताईस हजार मात्र)

अर्थात् कुल इन-राशि ₹ 2187746 हजार (दो अरब अठ्ठाई करोड़ सत्तर लाख छियालीस हजार

मात्र) में विहित निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री

राज्यपाल सहित स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वचनबद्ध मर्दों तथा बेलन, महगाई भला, अन्य भत्ते, विद्युत देय, जलकल/जलप्रसार, किराया,

पेशन, भोजन व्यय, मजदूरी तथा आउटसोर्सिंग आधार पर नियोजित कार्मिकों के वेतन हेतु व्यवसायिक

सेवाओं के लिये भुगतान आदि मर्दों की इन-राशि आवश्यकता के आधार पर व्यय किये जाने की वित्तीय

स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते हैं कि इन मर्दों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार

पर किरावों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुक्रम ही किया जाएगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में

अधिकृत इन-राशि से अधिक इन-राशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्ययभार सृजित

किया जाएगा।

2. अवचनबद्ध मर्दों के सम्बन्ध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मिलव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाएगा

और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मर्द के सम्बन्ध में मिलव्ययता हेतु स्पष्ट

योजना बना ली जायेगी और तदनुसार प्रत्येक मर्द के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित इन-राशि के सापेक्ष

वचन का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित की वचन सुनिश्चित की जायेगी। मानक मर्द-01-बेलन-03-महगाई

भत्ता-06-अन्य भत्ते से पुनर्वित्तियोग पूर्णतः वर्जित है।

3. केन्द्रीयित योजनाओं के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1489/XVII(4)/2017-2(10)/2017 दिनांक

17.08.2017 में निर्गत इन-राशि ₹ 583682 हजार के सापेक्ष समस्त योजनाओं हेतु अवशेष राज्यांश की

इन-राशि सम्मिलित की गई है तथा व्यय कर उपयोजिता प्रमाण पत्र तत्काल भारत सरकार एवं शासन की

उपलब्ध करायी जायेगी।

4. कपया यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आप अपने अधीनस्थ आह्वान वितरण अधिकारी को भी साफ़देवर के माध्यम से ही बजट जारी करते हुए वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 610/3(150)@XXV11(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि आवंटित की गई है। उक्त धनराशि का आह्वान/व्यय योजनागत भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित समयान्तर्गत भारत सरकार को उपयुक्त प्रमाण पर भी प्रेषित किया जायेगा।

6. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त प्रतिका के अन्तर्गत शासन या अन्य संसद अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए। स्वीकृत धनराशि का व्यय पूर्व में समाप्त मदों में स्वीकृत की गई धनराशि के पूर्ण व्यय हो जाने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये कदापि न छोड़ी जाय।

8. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिंदु में यादें वह वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में, सम्पूर्ण मुख्य/तृ/उप तथा विस्तृत शीर्षक की अधिकतम किया जाए तथा प्रत्येक बिंदु में दृष्टिहीन और लाल स्पाही से राजस्व एवं पूर्वी शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कायालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

9. संलग्नक में विभिन्न लेखाशीर्षकों में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर ले कि धनराशि परिधिगत कार्यालयों को तत्काल अवसृत कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

10. भारत सरकार व अन्य संस्थाओं से पूर्णतः अथवा आंशिक आधार पर पंक्षित योजनाओं अथवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा धनावदन की स्वीकृति उसी दशा में दी जाय जब भारत सरकार अथवा अन्य सम्बन्धित संस्थाओं से योजना के कार्यान्वयन हेतु किस्त आवंटित कर दी गई हो अथवा कार्यान्वयन और धनराशि आवंटित करने के सम्बन्ध में औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

11. किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का ब्यौर शासन की सहमति के किसी भी प्रकार से पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

12. उपर्युक्त धनराशि वित्तीय हस्त प्रतिका के प्रावधानों के अन्तर्गत समय साक्षी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा तक लिये जाने का दायित्व आपका होगा।

14. धी0एम0-8 पर संकलित मासिक सूचनायें नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

15. इस सम्बन्ध में होने वाला चार्ज वितीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम से जाला जायेगा।

16. यह आदेश शासनादेश संख्या 183/xxvii-1/2012 दिनांक 28-3-2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में [www.cts.uk.gov.in](http://www.cts.uk.gov.in) से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत क्रमशः विशेष नम्बर/अर्जिटमेन्ट आर्क0डी0 5171150001, 51711300002 एवं 51711310003 दिनांक 01.11.2017 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

#### संलग्नक-यथोपरि

- संख्या-1963 (1)XVII(4)/2017-2(10)/2017-TC तद्विनांक
- प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदार), उत्तराखण्ड, देहरादून।
  2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  3. वित्त निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड देहरादून।
  4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
  5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
  6. वित्त-1 एवं 5/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
  7. सार्डवर डैजरी, लक्ष्मी रोड, जालनवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड।
  8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गाई फाईल।

भवदीया  
(राधा रतौडी)  
प्रमुख सचिव

आज्ञा से  
(विष्णु शर्मा)  
अपर सचिव